**मूल हिंदी में**

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3535**

10.08.2026 को उत्तर के लिए

**बिहार में अधिकतम तापमान वाले जिलों से संबंधित आंकड़े**

3535 **श्री सुधाकर सिंहः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य में अधिकतम तापमान दर्ज करने वाले जिलों की पहचान की है और यदि हां, तो विगत 10 वर्षों के तापमान से संबंधित आंकड़ों के साथ उक्त जिलों की सूची क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बढ़ते तापमान और लू के प्रभाव को कम करने के लिए बक्सर, रोहतास और कैमूर सहित अत्यधिक प्रभावित जिलों के लिए किसी विशेष कार्ययोजना या कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया है;

(ग) विगत 10 वर्षों के दौरान बिहार में तापमान में वृद्धि के क्या कारण हैं, और क्या इस संबंध में कोई जांच या अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो बक्सर, रोहतास और कैमूर सहित राज्य के सभी जिलों में तापमान नियंत्रण, वन आच्छादित क्षेत्र के विस्तार, जल संरक्षण और जलवायु अनुकूलन से संबंधित कार्यों पर गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार खर्च की गई निधि का ब्यौरा क्या है और इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा प्रकाशित जलवायु संवेदनशीलता और ऋतु अनुसार मौसम की निगरानी रिपोर्टों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी बिहार के रोहतास (विशेष रूप से देहरी), बक्सर, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में लगातार सबसे अधिकतम तापमान और भीषण लू की स्थिति को रिपोर्ट दर्ज की जाती है। बिहार मौसम सेवा केंद्र (बीएमएसके), बिहार सरकार ने बिहार के सभी ब्लॉकों में स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूसी) स्थापित किए हैं, जिसका उद्देश्य लक्षित सूचना अभियानों और स्थानीय प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से बिहार की मौसम और जलवायु सेवाओं को मजबूत करना, समुदाय-नेतृत्व वाली अनुकूलन योजना और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना, नागरिकों और संस्थानों को सक्रिय, जीवन रक्षक और आर्थिक रूप से टिकाऊ निर्णय लेने में मार्गदर्शन करना है। पिछले 10 वर्षों के तापमान संबंधी आंकड़े मौसम केंद्र पटना, आईएमडी पर https://mausam.imd.gov.in/patna/ पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ): बिहार सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य के लिए लू का मानचित्रण किया है और बिहार राज्य लू कार्य योजना तैयार की है। भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाइयों के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करने वाली राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अनुरूप, बिहार सरकार ने राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार की है। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित क्षेत्रों के लिए तैयार की गई एसएपीसीसी कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु। संबंधित राज्यों और भारत सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ अभिकरण सुनिश्चित करते हुए, संबंधित क्षेत्रों के लिए अपनी योजना के व्यय में संसाधन उपलब्ध करवांएगी। इसके अलावा, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार राज्य के लिए एसएपीसीसी तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी है। साथ ही, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन' (एनएमएसकेसीसी) के तहत बिहार में 'राज्य जलवायु परिवर्तन सेल' (एससीसीसी) की स्थापना की है। एससीसीसी, बिहार राज्य को जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन करने, मानव क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जन जागरूकता कार्यक्रम, संस्थागत क्षमता निर्माण और राज्य द्वारा अपनी 'राज्य कार्य योजनाओं' के हिस्से के रूप में सतत विकास के लिए चुने गए कार्यों को लागू करने में मदद करता है। इस प्रोजेक्ट के तहत, ज़िला स्तर पर अध्ययन किए जाते हैं, जो एक सामान्य ढांचे का उपयोग करके जलवायु अनुकूलन योजना बनाने में उपयोगी होते हैं।

बिहार राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में बक्सर, रोहतास और कैमूर ज़िलों में कुल 1,63,04,932 पौधे लगाए गए, जिन पर 2,43,96,98,854 रुपये का खर्च आया।

इसके अलावा, केंद्र सरकार संबंधित मंत्रालयों के बजट के माध्यम से भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रीन कवर (हरियाली) के विस्तार, जल संरक्षण और जलवायु अनुकूलन से जुड़े कार्यों के लिए वित्त पोषण प्रदान करती है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष' से "बिहार में जलवायु-स्मार्ट गांवों को मुख्यधारा में लाकर जलवायु-स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने" के परियोजना के लिए 23.06 करोड़ रुपये की राशि मंज़ूर की। राज्य में कई अन्य योजनाएं भी लागू की जा रही हैं, जैसे कि सूक्ष्म-सिंचाई के लिए 'प्रति बूंद अधिक फसल', सतत कृषि के लिए 'परंपरागत कृषि विकास योजना' और राष्ट्रीय 'प्राकृतिक कृषि मिशन', जल सुरक्षा के लिए 'जल जीवन मिशन', पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और जैव विविधता संरक्षण में मदद के लिए 'प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण' (काम्पा) कार्यक्रम, और समुदाय-आधारित आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए 'आपदा मित्र योजनाएं भी राज्य में लागू की जा रही हैं।

****